E Content for the Student of Patliputra University.

Subject - Political Science

Class - B.A (Hons.), Part-I, Paper - I

Topic Liberal views of state

Dr. Umesh Chandra Shukla
Associate Prof. Pol. Sc.
R. R. S. College, Mokama

राज्य के संबंध में उदारवादी विचारधारा एक लोकप्रिय विचारधारा है। अधिकांश राज व्यवस्थाएँ अपने को उदारवाद से ही जोड़कर देखना चाहती हैं।

उदारवाद की पृष्ठभूमि में हमें लॉक, रूसो तथा फ्रांस की राज क्रांति (1789) के विचारों में देखने को मिल सकती है। लॉक और रूसो दोनों ही राज की उत्पत्ति के सामाजिकतावादी सिद्धांत से जुड़े होने के बावजूद हॉब्स की तरह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन नहीं करते हैं। लॉक ने व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार माना है, जिसे शासक द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है रूसो ने राज को जनता की "सामान्य इच्छा (General will)" पर आधारित होने की बात किया है। इसी प्रकार फ्रांस की क्रांति का लोकप्रिय नारा था, "स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व"

इस प्रकार इन विचारों ने स्वतंत्रता, समानता एवं लोकतंत्र के विचारों का बीजारोपण किया, जो उदारवाद का मूल आधार है।

उदारवाद व्यक्ति के व्यक्तित्व की गरिमा की स्थापना में विश्वास करता है। यह तबतक संभव नहीं है, जबतक आमजनता किसी तानाशाह या स्वेच्छाचारी शासक के नियंत्रण में हो। इसके लिए व्यक्ति को स्वतंत्रता एवं समानता की आवश्यकता है। जबतक लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने की स्वतंत्रता

नहीं होगी, इसी प्रकार अवसर की समानता नहीं होगी उदारवाद की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब विश्व के अधिकांश भागों में राजतंत्र, अधिनायकवाद, साम्राज्यवाद प्रचलित था, लोक स्वतंत्रता, समानता की बात सोच नहीं सकते थे, उन दिनों कुछ क्रांतियों की सफलता ने उदारवाद के रास्ते की उम्मीद जगाई। इनमें ग्रेट-ब्रिटेन की गौरव पूर्ण क्रांति (1688), अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम (1776) तथा फ्रांस की क्रांति (1789)।

19वीं सदी में धीरे धीरे अधिकांश राज्य स्वतंत्र हुए और राज्य की उदारवादी व्यवस्था का रुझान बढ़ा।

उदारवाद वस्तुतः लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही आधारित है। लोकतंत्र स्वतंत्रता और समानता पर सम्यक दृष्टि रखने की बात करता है। इसमें स्वतंत्रता का पलड़ा कुछ भारी रहता है क्योंकि आर्थिक समानता तथा सामाजिक समानता पर बल कम रहता है इसके स्थान पर अवसर की समानता का प्रावधान रहता है। इसके विपरीत समाजवादी व्यवस्था में स्वतंत्रता गौण हो जाती है तथा समानता पर विशेष बल रहता है।

उदारवादी व्यवस्था मौलिक रूप में राज्य के अहस्तक्षेप की नीति (Laissez-faire) की नीति में विश्वास करता है। इसके साथ-साथ Spencer की नीति survival of the fittest, struggle for existance में विश्वास करता है। इसी अर्थ में व्यवहारतः उदारवाद की नीति पूंजीवाद की नीति है। इसमें राज्य व्यवस्था का ढांचा लोकतांत्रिक रहता है।

वर्तमान समय में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विश्व की व्यवस्थाएँ दो [illegible] स्वरूप में देखी गई। समाजवादी एवं साम्यवादी व्यवस्था तथा दूसरा लोकतांत्रिक व्यवस्था। समाजवादी एवं साम्यवादी

व्यवस्था में लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव में तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। एक विचारधारा, एकदल तथा एक नेतृत्व के नाम पर व्यवस्था वस्तुतः तानाशाही हो गई।

इसके विपरीत स्वतंत्रता की महत्ता के कारण लोकतंत्र बहुदलीय व्यवस्था हो चुनाव के माध्यम से लोगों को सत्ता परिवर्तन करने देने का प्रावधान हो। लोग मौलिक अधिकारों का उपयोग कर अपना विकास एवं संरक्षण प्राप्त करते है। अतः यह व्यवस्था ज्यादा लोकप्रिय हुई। समानता के अधिकार तथा अन्य मौलिक अधिकारों एवं न्यायिक संरक्षण के कारण समाज हर तबके के लोगों को यह आकर्षित करने में सफल हो। 1990 के दशक में सोवियत संघ के साथ संपूर्ण विश्व में समाजवादी / साम्यवादी व्यवस्थाएँ प्रभावित हो गई।

उदारवादी राज्य व्यवस्था की निम्न लिखित विशेषताओं को चिन्हित किया जा सकता है —

(i) लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था.
(ii) स्वतंत्रता एवं समानता के बीच सामंजस्य का प्रावधान
(iii) मौलिक अधिकारों का प्रावधान
(iv) संवैधानिक व्यवस्था तथा मौलिक अधिकारों को संरक्षण देने के लिए निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान
(v) उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर कानूनी सीमाओं एवं शर्तों के साथ व्यक्तिगत नियंत्रण की सुविधा.

(

1990 के दशक के बाद उदारवादी राज्य व्यवस्था को नये रूप में मान्यता मिली। अब वैश्वीकरण, निजीकरण तथा खुलेपन के नये दौर में राज्य इसमें लोगों के साथ संबंधों के निर्धारण की प्रक्रिया पर सहमत हुए

विश्व व्यापार संगठन (W.T.O.) जैसी संस्था का निर्माण हुआ जो विश्व व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बना। राज्यों ने उद्योगों तथा व्यापार के लिए लाइसेंस परमिट राज की नीति छोड़ दी। इस संदर्भ में अधिक छूट के प्रावधान किये गये। बैंकिंग सेवाएँ उनके लिए उपलब्ध कराई गई। उत्पादित मालों पर पेटेंट का मार्क लगा, जिससे वे व्यापार का लाभ अपने शर्तों पर उठा सकें।

इस प्रकार वर्तमान समय में उदारवादी राज्य व्यवस्था नये दौर में पहुँच चुका है। इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण है आर्थिक क्रियाएँ और व्यापार। कोई एक राज्य नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व इसकी स्वीकृति प्रदान कर चुका है।